



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072025-264632
CG-DL-E-14072025-264632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]
No. 196]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ 19, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

फा न. 80-04/2022-एस.पी.-VI—

खेलो भारत नीति – 2025

1. प्रस्तावना

1.1 राष्ट्र निर्माण और समग्र विकास में खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हुए भारत सरकार ने एतद्वारा खेलो भारत नीति-2025 (राष्ट्रीय खेल नीति-2025) तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्र के नागरिकों की समग्र भलाई को बढ़ावा देते हुए उत्कृष्टता, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए खेलों की क्षमता का उपयोग करना है। राष्ट्रीय खेल नीति 2001, खेलो इंडिया स्कीम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) जैसी पिछली पहलों द्वारा रखी गई नींव पर निर्मित करते हुए, इस व्यापक नीति में एक एकीकृत और मजबूत खेल इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है जो जमीनी स्तर से ओलंपिक 2036 सहित ओलंपिक पोडियम तक प्रतिभाओं को निखारती है।

1.2 भारत, अपने अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, वैश्विक नेता बनने की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक के रूप में, वैश्विक युवा आबादी के पांचवें हिस्से (यानी 15-29 आयु वर्ग के

बीच) के साथ, भारत में राष्ट्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में खेलों का लाभ उठाने की अपार क्षमता है। खेलो भारत नीति-2025 को "विकसित भारत" में उल्लिखित सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

1.3 इस नीति में ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के हालिया प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया है। इसमें इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और खेलों में दीर्घकालिक सफलता के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है।

2. विजन और उद्देश्य

2.1 खेलो भारत नीति-2025 का विज़न है " राष्ट्र निर्माण के लिए खेल - राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करना"। इस नीति का उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेल संस्कृति और इकोसिस्टम को मजबूत करना, अंततः वैश्विक स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना, आर्थिक विकास के लिए खेलों का लाभ उठाना, सामाजिक विकास के लिए खेलों का उपयोग करना और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खेलों को एक जन आंदोलन बनाना है।

2.2 खेल नीति के कार्यान्वयन में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही महत्वपूर्ण लेकिन पूरक भूमिका निभाती हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने, वित्तीय और परिचालन सहायता प्रदान करने, विनियामक मानक स्थापित करने और सलाहकार मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रमुख स्पर्धाओं के लिए सुविधा भी प्रदान करती है और पूरे देश में खेल विकास की दिशा निर्धारित करने के लिये खाका बनाती है। जबकि, राज्य सरकारें क्षेत्रीय स्तर पर इन राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने, स्थानीय खेल अवसरचना का प्रबंधन करने और जमीनी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, स्थानीय कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय खेल नीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए और समग्र व्यापक और स्थानीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बनाया जाए।

2.3 इस विजन को साकार करने के लिए यह नीति कई प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है, जो नीचे दिए गए हैं:

- (i) जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी भागीदारी समूहों के लिए व्यापक खेल कार्यक्रम स्थापित करना।
- (ii) विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं और लीग का आयोजन करके एक मजबूत प्रतिस्पर्धी संरचना का निर्माण करना।
- (iii) खेल और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक साक्षरता पहल को लागू करना।
- (iv) भावी चैंपियनों को निखारने के लिए एक मजबूत प्रतिभा पहचान और विकास प्रणाली विकसित करना।
- (v) देश भर में खेल अवसरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
- (vi) खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए एथलीट-केंद्रित सहायता प्रणाली प्रदान करना।
- (vii) प्रदर्शन और स्वस्थता को बढ़ाने के लिए खेल विज्ञान, चिकित्सा और नवाचार को बढ़ावा देना।
- (viii) खेल क्षेत्र में प्रशासन और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना।
- (ix) खेलों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण तंत्र में सुधार करना।
- (x) खेल-संबंधी उद्योगों और गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- (xi) खेलों के माध्यम से सामाजिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना।
- (xii) युवाओं के लिए खेल को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में स्थापित करना।
- (xiii) एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए खेल और फिटनेस गतिविधियों में बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- (xiv) चैंपियन एथलीटों के साथ-साथ सेवानिवृत्त एथलीटों को पुरस्कृत करने और महत्ता देने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना।
- (xv) खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों के रूप में कार्य करने हेतु एक रूपरेखा और दिशानिर्देश विकसित करना।

3. खेलो भारत नीति-2025 की रूपरेखा

खेलो भारत नीति-2025 पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य भारत के खेल परिदृश्य को बदलना है। सबसे पहले, यह अवसरचना, प्रतिभा पहचान और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर वैश्विक मंच पर राष्ट्र की उत्कृष्टता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए खेल पर्यटन, विनिर्माण और खेल प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खेलों का लाभ उठाने पर जोर देता है। तीसरा, सामाजिक विकास के लिए खेल, खेलों के माध्यम से समावेशिता, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देकर सामाजिक सामंजस्य निर्मित करते हैं। चौथा, खेल - एक जन आंदोलन समुदायों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना चाहता है,

जिससे खेल एक सांस्कृतिक आधारशिला बन सके। अंततः, खेलो भारत नीति-2025 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) 2020 के साथ संरेखित है, जो छात्रों, युवाओं में समग्र विकास और जीवन कौशल के निर्माण के लिए शिक्षा के साथ खेल को एकीकृत करता है, जिससे शैक्षणिक और एथलेटिक उत्कृष्टता दोनों को बढ़ावा मिलता है। उपरोक्त प्रत्येक रूपरेखा को बाद के पैराग्राफ में समझाया गया है।

3.1 वैश्विक मंच पर राष्ट्र की उत्कृष्टता

ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेल संस्कृति और इकोसिस्टम को मजबूत करना खेलो भारत नीति-2025 का मुख्य फोकस है। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य भारतीय समाज के ताने-बाने में खेलों को गहराई से एकीकृत करना है, जिससे जमीनी स्तर तक सभी के लिए पहुँच और अवसर सुनिश्चित हो सकें। ब्लॉक स्तर पर, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। स्कूलों, स्थानीय क्लबों और सामुदायिक केंद्रों को लक्षित करते हुए सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक-स्तरीय खेल कार्यक्रम स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। नियमित खेल उत्सव, प्रतिभा खोज शिविर और प्रतियोगिताएँ व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगी और शुरुआती चरण में होनहार एथलीटों की पहचान करने में मदद करेंगी। इसके अतिरिक्त, खेल अवसरचना विकसित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में भी सुविधाओं तक पहुँच हो, जिससे समावेशिता और सहभागिता को बढ़ावा मिले। खेलो भारत नीति-2025 भारत में विभिन्न स्तरों पर खेल संस्कृति और इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार करती है। नीति में शारीरिक साक्षरता, आउटरीच और जागरूकता को बढ़ावा देते हुए खेल कार्यक्रमों, लीगों और प्रतियोगिताओं को विकसित करने के उद्देश्य से कई पहल शामिल हैं।

- (i) खेल कार्यक्रम: खेलो भारत नीति-2025 सभी भागीदारी समूहों में समावेशी खेल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है, जो इकाई स्तर से शुरू होकर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तारित होता है। इसमें संरचित खेल कार्यक्रम विकसित करना शामिल है जो प्रत्येक व्यक्ति की खेल के अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए विभिन्न आयु समूहों, योग्यताओं और कौशल स्तरों को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय खेल परिषद (एनएसएफ) खेल विकास पिरामिड के विभिन्न स्तरों पर मजबूत कार्यक्रम खाका बनाने में मदद करेंगे, जिससे जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तरों तक निर्बाध प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
- (ii) खेल लीग और प्रतियोगिताएं: यह नीति समुदाय, शैक्षणिक संस्थान और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं और लीगों की स्थापना पर बल देती है। इन प्रतियोगिताओं के लिए एक स्थायी रूपरेखा विकसित करने के लिए एनएसएफ को सक्षम करके, खेलो भारत नीति-2025 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देना और एथलीटों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए नियमित अवसर प्रदान करना है। एक सुसंगत और प्रभावी प्रतिस्पर्धी संरचना सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग से इस ढाँचे को विकसित किया जाएगा।
- (iii) फिजिकल साक्षरता: बचपन से ही फिजिकल साक्षरता प्रदान करने की कार्ययोजना नीति का एक केंद्रीय घटक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, खेल और शारीरिक साक्षरता को शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुख विषयों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों में शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्यता के प्रति आजीवन रुचि विकसित हो।
- (iv) आउटरीच और जागरूकता: आम जनता को जोड़ने और प्रसिद्ध राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल सितारों के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करने के लिए नियमित खेल आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खेलों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने और लोगों के बीच शारीरिक रूप से सक्रिय जीवनशैली के लाभों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और ज्ञान सत्र आयोजित किए जाएंगे।
- (v) प्रमुख खेल स्पर्धाएं: भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई), विभिन्न एनएसएफ, राज्य सरकारों और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संगत संगठन और निजी संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए प्रमुख खेल स्पर्धाओं के आयोजन के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी ढाँचा तैयार करना शामिल है जिससे इन आयोजनों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए और प्रभावी तौर पर समाज की बेहतरी हो।
- (vi) मजबूत खेल प्रोत्साहन संस्थान: परिचालन दक्षता, पेशेवर प्रबंधन, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके एनएसएफ सहित देश में खेल प्रोत्साहन संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए निर्बाध कामकाज और प्रभावी समस्या निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की निगरानी एजेंसियों के संवर्धन की आवश्यकता होगी।
- (vii) एथलीट-केंद्रित खेल विकास: एथलीटों के लिए एक सुलभ और कुशल खेल सहायता इकोसिस्टम बनाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की जाएगी। इसमें व्यापक कोचिंग, वैज्ञानिक सहायता और एथलीट के मुद्दों के समाधान हेतु सुव्यवस्थित तंत्र शामिल हैं। नीति में संभावित और शीर्ष एथलीटों की सहायता के लिए एक सरलीकृत फंडिंग रूपरेखा का भी प्रस्ताव है, साथ ही एथलीटों को उनके करियर के विभिन्न चरणों में सहायता करने के लिए तंत्र, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद की सहायता भी शामिल है।
- (viii) खेल कार्मिक: प्रशिक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रभावी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से खेल कार्मिक इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा। इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रमाणन और पुनः प्रमाणन के माध्यम से कोचों के निरंतर कौशल उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होगा। कोचिंग पाठ्यक्रम

में आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों, खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करने पर जोर दिया जाएगा। ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराने के लिए वैश्विक खेल संस्थानों और परिसंघों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरह रेफरी / अंपायर आदि सहित अन्य सहायक कर्मियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रयास किए जाएंगे। खेल सहायक इकोसिस्टम जैसे कि खेल प्रशासकों, प्रबंधकों, कमेंटेटोरों, एडीटर आदि के कौशल उन्नयन पर बल दिया जाएगा।

- (ix) सुरक्षा, नैतिकता और व्यावसायिकता: खेल सुरक्षा, नैतिकता लैंगिक समानता, शिकायत निवारण और व्यावसायिकता पर केंद्रित संस्थानों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें एंटी-डोपिंग, अंपायरिंग और पैरा-क्लासिफिकेशन के लिए कार्यक्रम विकसित करना, साथ ही इन क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना शामिल होगा। सुरक्षित और नैतिक खेल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों का गठन किया जाएगा।
- (x) खेल विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार: भारत की खेल विकास रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में खेल विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल चिकित्सा और प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। एथलीट के प्रदर्शन और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इन क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रगति जैसे बायोमैकेनिक्स, आघात रोकथाम और रिकवरी, पोषण, प्रदर्शन विश्लेषण और मानसिक कंडीशनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों को हैकथॉन और अनुसंधान अनुदान जैसी पहलों के साथ अंतःविषयक खेल-संबंधी अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लक्षित नवाचार प्रयासों की देखरेख के लिए एक खेल नवाचार टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों में खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- (xi) चैंपियन एथलीटों के लिए पुरस्कार एवं मान्यता: चैंपियन और सेवानिवृत्त एथलीटों को पुरस्कृत करने और महत्ता देने के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी, साथ ही सरकारी सेवाओं में एथलीटों की नियुक्ति के लिए एक भर्ती तंत्र भी स्थापित किया जाएगा।
- (xii) खेल विकास में शैक्षणिक संस्थान: शैक्षणिक संस्थानों को खेल विकास के लिए फीडर संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, जिसमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं की जल्द पहचान करने के लिए रूपरेखाएँ होंगी। एनएसएफ और अन्य खेल प्रोत्साहन एजेंसियों को छात्रों के लिए खेल गतिविधियों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संरचित खेल प्रशोत्तरी, सामान्य ज्ञान आदि सहित इंटरैक्टिव सहभागिता के माध्यम से खेलों से संबंधित ज्ञान का प्रसार किया जाएगा।
- (xiii) खेल विकास के लिए वित्तपोषण तंत्र को मजबूत करना: इस नीति में वित्तपोषण तंत्र को नया रूप देने का प्रस्ताव है, जिसमें "एक एथलीट को गोद लेना", "एक जिला गोद लेना", "एक स्थल को गोद लेना", "वन कारपोरेट-वन स्पोर्ट" और "वन पीएसयू-वन स्टेट" जैसी नवीन पहल, जहां व्यवहार्य हो, शामिल हैं। वित्तपोषित गतिविधियों की रणनीति बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक निगरानी निकाय या तंत्र, जहां आवश्यकता हो, का गठन किया जाएगा, जिससे सीएसआर सहित खेल विकास के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।
- (xiv) प्रतिभा खोज एवं विकास: खेलो भारत नीति-2025 का उद्देश्य एनएसएफ, राज्य, शैक्षणिक संस्थान, निजी संगठनों जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों को शामिल करते हुए खेल प्रतिभा खोज और विकास गतिविधियों का विस्तार करना है। प्रतिभा पहचान, विकास और निगरानी की सुविधा प्रदान करने वाला एक राष्ट्रीय मंच भी विकसित किया जाएगा जो एकल माध्यम के रूप में कार्य करेगा। शैक्षणिक संस्थानों के साथ एकीकरण और एथलीटों के लिए एक सहज ट्रांजीशन तंत्र प्रमुख घटक होंगे।
- (xv) खेल अवसंरचना: इस नीति में खेल सुविधाओं तक समान पहुंच पर जोर दिया गया है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक विषमताओं के बावजूद ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक अवसंरचना विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जनसांख्यिकी, कार्मिक, पिछले प्रदर्शन आदि जैसे क्षेत्रीय आंकड़ों के आधार पर उच्च प्रदर्शन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
- (xvi) जिले एवं राज्य: राज्यों और जिलों को अपने खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय खेल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मॉडल खेल राज्य और मॉडल जिला कार्यक्रम जैसी पहल शामिल हैं।
- (xvii) पैरा-स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता: पैरा-स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता के लिए एथलीट मार्ग और कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे और उन्हें लागू किया जाएगा। मुख्य फोकस डोमेन में दिव्यांगों के लिए शारीरिक साक्षरता, पैरा-स्पोर्ट्स में जमीनी स्तर पर खेल विकास, विशिष्ट पैरा-स्पोर्ट्स विकास, पैरा-स्पोर्ट्स अनुकूल खेल अवसंरचना आदि शामिल होंगे।

3.2 आर्थिक विकास के लिए खेल

खेल आर्थिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई रणनीतियाँ इस प्रभाव को बढ़ा सकती हैं। खेलों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की पहल में पर्यटन, उद्यमिता, विनिर्माण आदि सहित विभिन्न उपाय शामिल हैं। इनका उल्लेख निम्नानुसार है:

- (i) **प्रमुख खेल स्पर्धाओं के माध्यम से खेल पर्यटन:** भारत को वैश्विक खेल पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, प्रमुख खेल स्पर्धाओं से लाभ उठाना आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करके भारत अपने पर्यटन क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है, नौकरियों का सृजन कर सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित कर सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों/गेम्स की मेजबानी की जाएगी जो पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं और देश की वैश्विक छवि को बढ़ा सकते हैं।
- (ii) **मजबूत खेल उपकरण विनिर्माण इकोसिस्टम:** आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र विकसित करना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी राष्ट्रीय स्कीमों के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया जाएगा जो नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए खेल उपकरणों के विनिर्माण और वितरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता में और वृद्धि होगी।
- (iii) **मजबूत खेल स्टार्टअप और उद्यमिता वातावरण:** खेल स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एक संपन्न वातावरण को बढ़ावा देना नवाचार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खरीद कार्यक्रम, इनोवेशन हैकथॉन, स्पोर्ट्स इनक्यूबेटर प्रोग्राम जैसे सरकारी पहल स्टार्टअप के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी। खेल विकास में योगदान देने वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने, उन्हें सलाह, संसाधन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने के लिए स्पोर्ट्स स्टार्टअप और ऑनट्रेप्रेनरशिप एक्सीलरेटर प्रोग्राम की स्थापना की जाएगी।
- (iv) **हार्ड और सॉफ्ट खेल संपत्तियों की प्रचालनात्मक और वित्तीय स्थिरता:** खेल अवसंरचना की वित्तीय स्थिरता और परिचालन प्रचालनात्मक सुनिश्चित करना उनकी दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए हार्ड (स्टेडियम, एरेना) और सॉफ्ट (डिजिटल प्लेटफॉर्म, सामुदायिक कार्यक्रम) दोनों खेल संपत्तियों का मूलीकरण किया जाएगा। प्रभावी प्रबंधन और रणनीतिक साझेदारी राजस्व प्रवाह को बढ़ाएगी और उच्च परिचालन मानकों को बनाए रखेगी।
- (v) **नवाचार को मान्यता :** डिजिटल प्रौद्योगिकी, किफायती उत्पाद और समावेशिता जैसे विभिन्न उभरते क्षेत्रों में खेलों से जुड़े नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (vi) **वैश्विक खेल गंतव्य :** भारत की विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों का लाभ उठाकर इसे एक प्रमुख वैश्विक खेल गंतव्य में बदला जा सकता है। अद्वितीय विशेषताओं वाले क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा - जैसे शीतकालीन खेलों के लिए हिमालयी राज्य, बीच खेलों के लिए केरल और गोवा, और साहसिक खेलों के लिए उत्तराखंड। इससे भारत वैश्विक एथलीटों और पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिससे इसकी प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा।
- (vii) **खेल व्यवसाय सलाहकार समूह :** खेल उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए संबंधित मंत्रालयों, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए खेल व्यवसाय सलाहकार समूह की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। यह समिति रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगी, सहयोग की सुविधा प्रदान करेगी और देश भर में खेल व्यवसाय गतिविधियों का विस्तार करने के उद्देश्य से नीतियों और पहलों के कार्यान्वयन में सहायता करेगी।

3.3 सामाजिक विकास के लिए खेल

खेलों का एकीकृत शक्ति के रूप में उपयोग करके वैश्विक शांति और आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सकता है। समावेशिता पर जोर देने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी व्यक्तियों को, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के समान अवसर मिले। यह समावेशी दृष्टिकोण, खेल करियर और शैक्षिक मार्गों को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ मिलकर, युवाओं की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और समाज की सकारात्मकता में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है।

- (i) **कम प्रतिनिधित्व वाले जन संख्या समूहों की भागीदारी के लिए बाधाएं कम करना :** महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जनजातीय समुदायों और शारीरिक या मनोवैज्ञानिक चुनौतियों वाले लोगों जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बीच खेलों में समावेशिता को बढ़ावा देने और भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाओं सहित समर्पित खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऐसी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव बाधाओं को काफी हद तक कम कर सकता है और उनके बीच सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है। इसके अतिरिक्त, नियमित खेल लीग आयोजित की जाएंगी जो विशेष रूप से इन समूहों के लिए जुड़ाव को बढ़ावा देने और उनकी भागीदारी के लिए निरंतर अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। एक सुरक्षित और समावेशी खेल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों को विकसित करना और लागू करना सभी प्रतिभागियों के लिए एक स्वागत योग्य माहौल बनाने और भेदभाव से बचाने के लिए आवश्यक है।
- (ii) **देशज खेलों को बढ़ावा देना :** विभिन्न राज्यों के देशज खेलों के लिए मान्यता और समर्थन का विस्तार भारत के खेल परिदृश्य को समृद्ध कर सकता है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सकता है। भारत में विभिन्न खेलों की ऐतिहासिकता और विकास का दस्तावेजीकरण करने से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इन खेलों के लिए अवसंरचना को मजबूत करना, कर्मियों को प्रशिक्षित करना और एक मजबूत प्रतिस्पर्धा ढांचा स्थापित करना उनकी प्रोफाइल को बढ़ाने और उनकी

स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। देशज खेलों के प्रचार और विकास में निवेश न केवल सांस्कृतिक विविधता का प्रचार करेगा बल्कि प्रतिभा खोज और सामुदायिक जुड़ाव के लिए नए रास्ते भी प्रदान करेगा।

- (iii) **कम प्रतिनिधित्व वाली जनसंख्या हेतु प्रतिभा विकास पहल :** कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए तैयार एक व्यापक प्रतिभा विकास तंत्र स्थापित किया जाएगा जो देश भर में खेल प्रतिभाओं के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। विशिष्ट खेलों में प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मानवशास्त्रीय, आनुवांशिक और अन्य कारकों पर विचार करते हुए जनजातीय प्रतिभा विकास पहल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनजातीय खेल और महिलाओं के लिए खेल जैसे लक्षित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो इन समूहों से प्रतिभा दिखाने और संभावित एथलीटों की पहचान करने के लिए मंच प्रदान करेंगे। इन पहलों से भागीदारी की कमियों को दूर करने और अधिक समावेशी खेल माहौल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- (iv) **खेल के माध्यम से शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमलाप :** खेल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं। ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक विकास प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल भारतीय प्रवासियों और भारत के बीच एक सबल पुल के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे स्थायी भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए, विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों के लिए और उनके बीच समर्पित खेल स्पर्धाओं और लीग आयोजित किए जा सकते हैं। जहाँ भी संभव हो, विदेशों में रहने वाले होनहार और प्रमुख भारतीय मूल के एथलीटों को वापस आने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ मिलकर, ये प्रयास खेल को सांस्कृतिक कूटनीति और राष्ट्र निर्माण के एक सतत उपकरण में बदल सकते हैं, जिससे विश्व में भारत की पहचान मजबूत होगी।
- (v) **मुख्य धारा के करियर के रूप में खेल और संबद्ध सेवाओं को बढ़ावा देना :** करियर विकल्प के रूप में खेल की मान्यता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए संरचित ढांचे और नियमों के माध्यम से खेल पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। राज्यों और अन्य हितधारकों को खेल शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो उद्योग में अधिक मार्ग प्रदान करेगा। खेल प्रमाणपत्रों, डिग्री, पाठ्यक्रमों और नौकरी रिक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय मंच के साथ-साथ युवाओं के बीच खेल करियर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संसाधन बनाने से करियर मार्गों को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। दोहरे करियर कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा जो शिक्षा और खेल को संतुलित करता है जो छात्रों को उनके एथलेटिक और शैक्षिक लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाने में भी सहायता करेगा।
- (vi) **खेल स्वयंसेवी कार्यक्रम :** युवाओं को खेल स्वयंसेवा में शामिल करने से सामुदायिक भागीदारी बढ़ सकती है और विभिन्न खेल स्कीमों में सहायता की जा सकती है। सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स एक्टिवेटर और एफआईटी इंडिया वालंटियर कार्यक्रम जैसे मजबूत खेल स्वयंसेवी तंत्र स्थापित किए जाएंगे। कोर्स क्रेडिट, इवेंट पास और चैंपियन एथलीटों से मिलने के अवसरों जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से स्वयंसेवकों को पहचानने और पुरस्कृत करने को बढ़ावा दिया जाएगा जो युवा व्यक्तियों को खेल क्षेत्र में योगदान देने और स्वयंसेवा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा।

3.4 खेल – एक जन आंदोलन

खेल एक प्रमुख अवकाश और मनोरंजन कार्यक्रमलाप के रूप में कार्य करते हुए शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक शक्तिशाली जन आंदोलन में बदल सकता है। खेलों के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से समग्र फिटनेस में सुधार होता है, स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम होती है और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नियमित शारीरिक कार्यक्रमलाप समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हुए तनाव, चिंता और अवसाद को कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त, खेल अवकाश और मनोरंजन का मूल्यवान स्रोत प्रदान करते हैं, जीवन को समृद्ध बनाते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।

- (i) इस आंदोलन को सहायता देने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों को उनके खेल और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय **फिटनेस रैंकिंग और इंडेक्सिंग** प्रणाली लागू की जाएगी। फिटनेस पहल में उत्कृष्टता और नवाचार लाने के लिए स्कूल फिटनेस इंडेक्स और फिट वर्कप्लेस इंडेक्स जैसे तंत्र विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, एक मजबूत **कार्मिक प्रशिक्षण और प्रमाणन** कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा क्योंकि यह प्रशिक्षकों और शिक्षकों को प्रभावी खेल और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने, स्वास्थ्य परिणामों और प्रतिभा पहचान को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- (ii) **राष्ट्रीय खेल परिसंच (एनएसएफ)** अपनी विधाओं को बढ़ावा देने और शारीरिक और मानसिक स्वस्थता पर ध्यान केंद्रित करने वाली रूपरेखा तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे। इसे स्कूल साँकर प्रोग्राम और टेनिस फॉर टॉट्स जैसी पहलों के माध्यम से हासिल किया जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कार्यस्थलों पर फिटनेस कार्यक्रमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जाएगी जो एफआईटी इंडिया इंपॉर्मेशन एंड नॉलेज हब जैसे संसाधन भंडार द्वारा समर्थित फिटनेस गतिविधियों की संरचित और लगातार डिलीवरी सुनिश्चित करेगी।

- (iii) **शारीरिक शिक्षा रूपरेखा** शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों और प्रतिभा विकास तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाकर नया रूप दिया जाएगा। दिशानिर्देशों और रूपरेखाओं के माध्यम से **खेल सुविधाओं तक पहुंच** में सुधार किया जाएगा जो अधिक सार्वजनिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगा और ब्लॉक और जिला स्तरों पर सामाजिक खेल केंद्रों की स्थापना में सहायता करेगा।
- (iv) **मॉडल खेल कार्यक्रम और स्पर्धाएं**, नियमित भागीदारी को प्रोत्साहित और सक्रिय जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पारिवारिक खेल वीकेंड और समय-समय पर सामुदायिक सहभागिता गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। **प्रतिभागिता की बाधाओं** को कम किया जाएगा और पहुंच को और बढ़ाने के लिए कम उपयोग की गई सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ उठाया जाएगा। अंत में, योग चैलेंज और 10,000 कदम प्रतिदिन चैलेंज जैसे **राष्ट्रीय- स्तर के कार्यक्रम** और डिजिटल पहल आयोजित की जाएंगी, जो बड़े पैमाने पर जुड़ाव को बढ़ावा देंगी और खेलों को सामुदायिक जीवन के एक केंद्रीय तत्व के रूप में मजबूत करेंगी, जो इसे एक सच्चे जन आंदोलन में बदल देंगी।

3.5 खेलो भारत नीति-2025 को एनईपी 2020 के साथ सुसंगत बनाने हेतु प्रमुख फोकस क्षेत्र

खेलो भारत नीति-2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु कई प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा। समग्र शिक्षा कार्यक्रम में खेल मॉड्यूल की रूपरेखा और प्रतिपादन की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेल और शारीरिक शिक्षा को समग्र पाठ्यक्रम में सहजता से एकीकृत किया जा सके। इस दृष्टिकोण से शैक्षणिक शिक्षा में शारीरिक फिटनेस और व्यक्तिगत विकास को जोड़कर छात्रों का संतुलित विकास संभव होगा।

- (i) स्कूलों में खेलों की व्यवस्था और प्रभाव को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में खेल समूहों और मंडलियों की सक्रिय भागीदारी की एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसमें स्थानीय खेल संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना और संरचित कार्यक्रम बनाना शामिल होगा जिससे शैक्षिक परिवेश के भीतर खेलों में भागीदारी और प्रतिभा विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- (ii) शिक्षकों के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और खेल शिक्षा के प्रभावी प्रतिपादन के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने से यह सुनिश्चित होगा कि वे छात्रों को सिखाने और प्रेरित करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, जिससे स्कूलों में खेल कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- (iii) खेल कार्यक्रमों के प्रभावी प्रतिपादन के लिए अवसंरचनात्मक और संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना और समय-सारणी विकसित करने हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क करने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करना, खेल के मैदान जैसे आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करना और नियमित आधार पर स्कूल-स्तरीय कार्यक्रमों को आयोजित करना शामिल होगा। सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और खेल संगठनों के बीच समन्वित प्रयास से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और शैक्षिक परिदृश्य में खेलों को एकीकृत करने के लिए एक स्थायी ढांचा बनाने में मदद मिलेगी।

4. खेलो भारत नीति-2025 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीतिक रूपरेखा

इस रणनीतिक रूपरेखा में मजबूत शासन, शिक्षा, तकनीकी एकीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत के खेल पारितंत्र को और अधिक विकसित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा शामिल है। इस रूपरेखा के प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं:

- (i) **मजबूत पेशेवर खेल अभिशासन, कार्यान्वयन और निगरानी** : ओलंपिक 2036 के लिए भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करने के उद्देश्य से शासन के लिए आवश्यक कानून सहित अपेक्षित विनियामक ढांचा स्थापित किया जाएगा। डोपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुरूप एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाएगा। खेल के क्षेत्र में नैतिक प्रथाओं, निष्पक्ष खेल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नियामक निकायों की स्थापना की जाएगी। इसमें खेल पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और निर्बाध संचालन को बढ़ावा देने, त्वरित कार्रवाई और मुद्दों का प्रभावी समाधान निकालने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों और अंतर-मंत्रालयी समितियों का गठन भी शामिल होगा।
- (ii) **मजबूत खेल शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार रूपरेखा** : भविष्य के एथलीटों और खेल पेशेवरों के लिए एक मजबूत आधार बनाने के लिए खेल शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर पर्याप्त बल दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है जो खेल प्रशिक्षण, प्रबंधन और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे खेल के क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रगतिशील और गतिशील दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।
- (iii) **तकनीकी हस्तक्षेप** : विभिन्न खेल स्कीमों और परियोजनाओं के आयोजन और उनकी निगरानी में दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मौजूदा प्लेटफार्मों में सुधार किया जाएगा। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डाटा संबंधी विश्लेषण करके प्रदर्शन की निगरानी और विश्लेषण करना है, जिससे खेल के क्षेत्र में

इष्टतम परिणाम और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वित कार्यक्रमों के लिए समय पर हस्तक्षेप करना संभव हो सकेगा।

- (iv) **राष्ट्रीय रूपरेखा और नियामक निकाय** : देश में खेलों के विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्पष्ट बेंचमार्क, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ एक मजबूत राष्ट्रीय संरचना स्थापित की जाएगी। यह जमीनी स्तर पर विकास, शीर्ष एथलीटों का प्रशिक्षण और अवसंरचनाओं में वृद्धि द्वारा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अतिरिक्त, यह खेल पारितंत्र में व्यापक और समावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर खेल लीग के आयोजन का समर्थन करेगा।
- (v) **निजी क्षेत्र की भागीदारी** : ऐसी नीतियों और स्कीमों को विकसित किया जाएगा जो खेल विकास गतिविधियों में निजी क्षेत्र से व्यापक भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें। इस भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, नीति संस्थाओं के लिए निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) देने के विचार को शामिल किया जाएगा, जिससे खेल विकास में उनकी भागीदारी आकर्षक और टिकाऊ दोनों बनी रहेगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देना है जहां देश के खेल बुनियादी ढांचे और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

5. निष्कर्ष

5.1 खेलो भारत नीति-2025 भारत में खेल विकास में क्रांति लाने हेतु लक्षित एक दूरदर्शी और व्यापक रूपरेखा का प्रतीक है। इसे राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए खेलों में प्राप्त उपलब्धियों को आर्थिक और सामाजिक प्रगति के व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस नीति में बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है जो अवसंरचना विकास, प्रतिभा पहचान, पोषण, शासन सुधार और जन भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देती है। खेलो भारत नीति-2025 का उद्देश्य भारत को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की मेजबानी करने के लिए एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना तथा अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी के साथ-साथ अपनी पदक तालिका में भी सुधार करना है।

5.2 खेलो भारत नीति-2025 राज्यों के लिए एक आदर्श नीति के रूप में काम करेगी, जिन्हें अपनी मौजूदा खेल नीति को संशोधित करने या इस नीति के अनुरूप नई खेल नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, समग्र सरकारी दृष्टिकोण का पालन करते हुए, इस नीति को खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र, नीतियों, योजनाओं आदि में कार्यान्वयन और एकीकरण की आवश्यकता है।

5.3 खेलो भारत नीति-2025 द्वारा रेखांकित इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, खेल परिसंघों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं और आम जनता सहित सभी संबंधित हितधारकों के एकीकृत प्रयास की आवश्यकता होगी। नीति की पहलों के सफल क्रियान्वयन में प्रत्येक हितधारक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सरकारी एजेंसियां आवश्यक नियामक ढांचा और वित्त पोषण प्रदान करेंगी, खेल परिसंघ प्रतिभा विकास और प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ाएंगे, निजी क्षेत्र संसाधनों और नवाचार में योगदान देंगे और जनता खेल गतिविधियों में शामिल होगी और उनका समर्थन करेगी। भारत इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी पूर्ण खेल क्षमता का दोहन कर सकता है, जिससे खेलों में देश की वैश्विक स्थिति में परिवर्तनकारी प्रभाव लाने का माहौल तैयार होगा और इसके समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

डा. शोभित जैन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS
(DEPARTMENT OF SPORTS)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 10 July, 2025

F. No. 80-04/2022-SP-VI—

KHELO BHARAT NITI - 2025

1. INTRODUCTION

- 1.1 The Government of India, recognizing the transformative power of sports in nation- building and holistic development, hereby formulates the Khelo Bharat Niti-2025 (National Sports Policy-2025). This policy aims to harness the potential of sports to drive excellence, economic growth and social progress while promoting the overall well-being of the nation's citizens. Building upon the foundations laid by previous initiatives such as the National Sports Policy-2001, the Khelo India Scheme and the Target Olympic Podium Scheme (TOPS), this comprehensive policy seeks to create an inclusive and robust sporting ecosystem that nurtures talent from the grassroots to the Olympic podium including Olympics 2036.
- 1.2 India, with its favorable demographic dividend and rapidly growing economy, stands at a crucial juncture in its journey towards becoming a global leader. As one of the youngest nations in the world, with a fifth of the global youth population (i.e. between the age group 15-29), India possesses immense potential to leverage sports as a catalyst for national development. The Khelo Bharat Niti-2025 is designed to align with the principles outlined in the "**Viksit Bharat**".
- 1.3 The policy takes into account India's performances in major international competitions, including the Olympic Games, Paralympic Games, Commonwealth Games and Asian Games. It recognizes the need to build on these achievements and create a sustainable system for long-term success in sports.

2. VISION AND OBJECTIVES

- 2.1 The vision of the Khelo Bharat Niti-2025 is "**Sports for Nation Building – Harness the Power of Sports for Nation's Holistic Development**". This policy aims to strengthen the sporting culture and ecosystem from the grassroots to the national level, ultimately achieving excellence in sports on the global stage, leveraging sports for economic development, utilizing sports as a tool for social development and making sports a people's movement for health and well-being.
- 2.2 In sports policy implementation, the Union Government and State governments each play crucial yet complementary roles. The Union government is responsible for creating national policies, providing financial and operational support, establishing regulatory standards and offering advisory guidance. It also facilitates major events and develops frameworks that set the direction for sports development across the country. Whereas, State governments focus on implementing these national policies at the regional level, managing local sports infrastructure and organizing grassroots programs. They provide additional financial support, monitor local implementation and intervene to address specific regional needs. This collaboration ensures that national sports policies are effectively executed and adapted to meet both overall broad and local requirements.
- 2.3 To realize this vision, the policy focuses on several **key objectives**, which are given below:
 - (i) Establish comprehensive sports programs for all participation groups, from grassroots to elite levels.
 - (ii) Organize sports competitions and leagues at various levels, creating a robust competitive structure.
 - (iii) Implement physical literacy initiatives to promote a culture of sports and physical activity.
 - (iv) Develop a robust talent identification and development system to nurture future champions.
 - (v) Ensure equitable access to sports infrastructure across the country.
 - (vi) Provide athlete-centric support systems for the holistic development of sportspersons.
 - (vii) Promote sports science, medicine and innovation to enhance performance and well-being.
 - (viii) Strengthen governance and institutional frameworks in the sports sector.
 - (ix) Revamp funding mechanisms to ensure sustainable development of sports.
 - (x) Foster economic growth through sports-related industries and activities.
 - (xi) Promote social development and inclusion through sports.
 - (xii) Establish sports as a viable career option for youth.

- (xiii) Encourage mass participation in sports and fitness activities for a healthier nation.
- (xiv) Develop a robust mechanism to reward and recognize champion athletes as well as retired athletes.
- (xv) Develop a framework and guidelines for educational institutions to act as feeder institutes to impart sporting culture.

3. CONTOURS OF THE KHELO BHARAT NITI-2025

The Khelo Bharat Niti-2025 is built upon five key pillars that aim to transform India's sports landscape. First, it focuses on achieving Nation's Excellence on the Global Stage by enhancing infrastructure, talent identification and international competitiveness. Second, Sports for Economic Development emphasizes leveraging sports to boost industries such as tourism, manufacturing and sports technology. Third, Sports for Social Development promotes inclusivity, health and education through sports, fostering societal cohesion. Fourth, Sports – A People's Movement seeks to engage communities in physical activities, making sports a cultural cornerstone. Finally, the Khelo Bharat Niti-2025 aligns with the National Education Policy (NEP) 2020, integrating sports with education to nurture holistic development and life skills in students, youths, promoting both academic and athletic excellence. Each of the above contours are explained in the subsequent paragraphs.

3.1 Nation's Excellence on the Global Stage

Strengthening the sporting culture and ecosystem from the block level to the national level is a key focus of the Khelo Bharat Niti-2025. This comprehensive approach aims to integrate sports deeply into the fabric of Indian society, ensuring access and opportunities for all, starting from the grassroots levels. At the block level, community engagement is vital to fostering a sporting culture. Block-level sports programs need to be established to promote mass participation, targeting schools, local clubs and community centers. Regular sports festivals, talent scouting camps and competitions will encourage wide spread participation and help identify promising athletes at early stage. Additionally, sports infrastructure will be developed to ensure that even the most rural or remote areas have access to facilities, fostering inclusivity and engagement. The Khelo Bharat Niti-2025 outlines a comprehensive strategy for enhancing the sporting culture and ecosystem across various levels in India. The policy includes a range of initiatives aimed at bolstering sports programs, leagues and competitions, while fostering physical literacy, outreach and awareness.

- (i) **Sports Programs:** The Khelo Bharat Niti-2025 advocates for the implementation of inclusive sports programs across all participation groups, starting from the unit level and extending to educational institutions like schools, colleges, universities, etc. This involves developing structured sports programs that cater to different age groups, abilities and skill levels, ensuring that every individual has access to sporting opportunities. National Sports Federations (NSFs) will facilitate to create robust program frameworks at various levels of the sports development pyramid, promoting a seamless progression from grassroots to elite levels.
- (ii) **Sports Leagues & Competitions:** The policy emphasizes the establishment of sports competitions and leagues at the community, educational institution and district levels. By enabling NSFs to develop a sustainable framework for these competitions, the Khelo Bharat Niti-2025 aims to foster a competitive spirit and provide regular opportunities for athletes to showcase their skills. This framework will be developed in collaboration with all stakeholders to ensure a cohesive and effective competition structure.
- (iii) **Physical Literacy:** An action plan for imparting physical literacy from early childhood is a central component of the policy. In alignment with the National Education Policy 2020, sports and physical literacy will be developed as major subjects in educational institutions, ensuring that students develop a lifelong appreciation for physical activity and well-being.
- (iv) **Outreach & Awareness:** Regular sports outreach programs will be organized to engage the general public and provide opportunities to interact with renowned national/international sports stars. Awareness campaign and knowledge sessions will be conducted to encourage active participation in sports and promote the benefits of a physically active lifestyle amongst masses.
- (v) **Major Sporting Events:** A roadmap for organizing major sporting events, involving various stakeholders such as the Indian Olympic Association (IOA), Paralympic Committee of India (PCI), various NSFs, State governments and the other relevant organizations recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports (MoYAS) and private organizations will be prepared. This includes creating a sustainable framework to ensure that these events are executed effectively and generate tangible returns for betterment of society.
- (vi) **Strong Sports Promotion Institutions:** Sports promotion institutions in the country, including NSFs, will be strengthened by focusing on operational efficiency, professional management, transparency and financial sustainability. This will call for the enhancement of national-level monitoring agencies to ensure seamless functioning and effective issue redressal mechanisms.

- (vii) **Athlete-Centric Sports Development:** A framework will be established to create an accessible and efficient sports support ecosystem for athletes. This includes comprehensive coaching, scientific support and streamlined mechanisms for addressing athlete issues. The policy also proposes a simplified funding framework to support potential and elite athletes, along with mechanisms to aid athletes at different stages of their careers, including post-retirement support.
- (viii) **Sports Personnel:** The sports personnel ecosystem shall be strengthened through effective programs for training and development. This will include focusing on continuous skill upgradation of coaches through certification and re-certification through accredited national and international training programs, workshops and online modules. Emphasis will be placed on integrating modern training methodologies, sports science, technology and data analytics into coaching curricula. Partnerships with global sports institutions and federations will be encouraged to facilitate knowledge exchange and exposure to best practices. Similarly efforts will be instituted for skill up gradation of other support personnel including referees / umpires, etc. Skill enhancement in sports support ecosystem will be emphasized such as for sports administrators, managers, commentators, editors, etc.
- (ix) **Safety, Ethics & Professionalism:** Strengthening institutions focused on sports safety, ethics, gender parity, grievance redressal and professionalism will be prioritized. This will include developing programs for anti-doping, officiating and para-classification, as well as encouraging research in these areas. National agencies will be formed to ensure a safe and ethical sports environment.
- (x) **Sports Science, Medicine and Technology, Research & Innovation:** Sports science, sports psychology, sports medicine and technology will be actively promoted as integral components of India's sports development strategy. Cutting-edge advancements in these areas such as biomechanics, injury prevention and recovery, nutrition, performance analytics and mental conditioning will be encouraged to enhance athlete performance and well-being. Educational institutions will be encouraged to undertake interdisciplinary sports-related research with initiatives such as hackathons and research grants. A Sports Innovation Task Force will be established to oversee targeted innovation efforts. Facilities for sports science and sports medicine will be provisioned in major training centers.
- (xi) **Rewards & Recognition for Champion Athletes:** A framework for rewarding and recognizing champion and retired athletes will be established, alongside a recruitment mechanism for hiring athletes in government services.
- (xii) **Educational Institutions in Sports Development:** Educational institutions will be guided to act as feeder institutes for sports development, with frameworks to foster a sporting culture and identify talent early. NSFs and other sports promotion agencies will be encouraged to organize sporting activities for students. Knowledge about sports to be disseminated through interactive engagement including structured Sports Quizzes, Trivia, etc.
- (xiii) **Strengthening Funding Mechanism for Sports Development:** The policy proposes a revamped funding mechanism, including innovative initiatives such as "Adopt an Athlete", "Adopt a District", "Adopt a Venue", "One Corporate-One Sport", "One PSU-One State", etc. wherever feasible. An oversight body or mechanism, if required, may be formed to strategize, execute and supervise funded activities, ensuring a collaborative approach to sports development including CSR.
- (xiv) **Talent Search & Development:** The Khelo Bharat Niti-2025 aims to expand sports talent search and development activities involving important stakeholders like NSFs, States, educational institutes, private organizations. A National platform that facilitates talent identification, development and monitoring will also be developed to act as a single window. Integration with educational institutions and a smooth transition mechanism for athletes will be key components.
- (xv) **Sports Infrastructure:** The policy emphasizes equitable access to sports facilities, with a focus on infrastructure development from block to state levels irrespective of economic, social and geographic disparities. A targeted approach will be adopted to address high-performance needs based on regional data like demographic, personnel, previous performance etc.
- (xvi) **Districts & States:** States and districts will be encouraged to strengthen their sporting ecosystems, with initiatives such as Model Sports State and Model District programs designed to enhance local sports capabilities.
- (xvii) **Excellence in Para-Sports:** Athlete pathways and programs will be formulated and implemented for excellence in Para-Sports. The major focus domain will include physical literacy for the differently-abled, grassroots sports development in para-sports, elite para-sports development, para-sports compliant sports infrastructure, etc.

3.2 Sports for Economic Development

Sports play a pivotal role in driving economic development and several strategies can enhance this impact. The initiatives for promoting economic development through sports encompasses various measures including tourism, entrepreneurship, manufacturing, etc. These are enumerated below:

- (i) **Sports Tourism through major Sporting Events:** To position India as a global sports tourism hub, it's essential to capitalize on major sporting events. By attracting international participants and spectators, India can significantly boost its tourism sector, create jobs and stimulate local economies. To achieve this goal, major International tournaments/games will be hosted in India which can generate substantial revenue and enhance the country's global image.
- (ii) **Strong Sports Equipment Manufacturing Ecosystem:** Developing a robust sports equipment manufacturing sector is crucial for economic growth. Integrating this sector with national schemes such as "Make in India" and "Atmanirbhar Bharat" will be emphasized which can drive innovation and create significant job opportunities. Additionally, the manufacturing and distribution of sports equipment shall be encouraged to ensure high standards, which will further enhance product quality and market competitiveness.
- (iii) **Strong Sports Startup & Entrepreneurship Environment:** Fostering a thriving environment for sports startups and entrepreneurs is vital for innovation and growth. Government initiatives such as procurement programs, innovation hackathons, sports incubator programs, etc. will provide the necessary support for startups. Sports Startup & Entrepreneurship Accelerator Program shall be established to further promote ventures that contribute to sports development, providing them with mentorship, resources and networking opportunities.
- (iv) **Operational & Financial Sustainability of Hard & Soft Sports Assets:** Ensuring the financial sustainability and operational excellence of sports infrastructure is essential for their long-term success. Both hard (stadiums, arenas) and soft (digital platforms, community programs) sports assets shall be considered to monetized to attract private investment through Public-Private Partnership (PPP) model and increase participation. Effective management and strategic partnerships will enhance revenue streams and maintain high operational standards.
- (v) **Recognition for Innovation:** Innovation in sports will be encouraged in various emerging areas such as digital technology, affordable products and inclusivity.
- (vi) **Global Sports Destination:** Leveraging India's diverse geographic and climatic conditions can transform it into a premier global sports destination. Regions with unique attributes shall be promoted —such as Himalayan States for winter sports, the coastal States for beach sports and hill states for adventure sports. By this, global athletes and tourists, will be attracted.
- (vii) **Sports Business Advisory Group:** Efforts shall be made to establish Sports Business Advisory Group comprising representatives from relevant Ministries, the private sector and other stakeholders for fostering the growth of the sports industry. This committee will provide strategic guidance, facilitate collaboration and support the implementation of policies and initiatives aimed at expanding sports business activities across the country.

3.3 Sports for Social Development

By leveraging sports as a unifying force, global peace and mutual understanding can be promoted. Emphasizing inclusivity ensures that all individuals, regardless of background, have equal opportunities to participate and excel. This inclusive approach, combined with efforts to promote sports careers and educational pathways, paves the way for the prosperity of youth, empowering them to achieve their full potential and contribute to positivity of society.

- (i) **Reduced Barriers for Participation of Underrepresented Population Groups:** To foster inclusivity and increase participation in sports among underrepresented groups such as women, economically weaker sections, tribal communities and those with physical or psychological challenge, dedicated sports facilities will be established along with services tailored to their unique needs. Creating and maintaining such facilities can significantly reduce barriers and promote active participation among them. Additionally, regular sporting leagues will be organized which are specifically designed for these groups to boost engagement and provide ongoing opportunities for their involvement. Developing and enforcing guidelines to be undertaken to ensure a safe and inclusive sports environment is essential to safeguard against discrimination and creating a welcoming atmosphere for all participants.
- (ii) **Promotion of Indigenous Sports and Games:** Expanding the recognition and support for indigenous games from various states can enrich India's sports landscape and preserve the cultural heritage. Research will be promoted for documenting the historical roots and development of various games in India. Strengthening the infrastructure, training personnel and establishing a robust competition framework for these games will be

ensured to help elevate their profile and ensure their sustainability. Investing in the promotion and development of indigenous games will not only celebrates cultural diversity but shall also provide new avenues for talent discovery and community engagement.

- (iii) **Underrepresented Population Talent Development Initiatives:** A comprehensive talent development mechanism tailored for underrepresented groups shall be established which is vital for nurturing sports talent across the country. Special focus shall be given to tribal talent development initiatives, considering anthropometric, genetic and other factors that may influence performance in specific sports. Targeted events, such as tribal games and women's games, will be organized that will provide platforms for showcasing talent and identifying potential athletes from these groups. These initiatives will help bridge participation gaps and foster a more inclusive sporting environment.
- (iv) **Peace & International Cooperation Activities through Sports:** Sports can serve as a powerful tool for international diplomacy and cooperation. International sports exchange programs will be promoted to allow knowledge sharing, capacity building and collaborative development efforts. Sports can serve as a powerful bridge between the Indian diaspora and India, fostering enduring emotional, cultural and social connections. To strengthen this bond, dedicated sporting events and leagues can be organized specifically for and among the Indian diaspora. Wherever feasible, promising and prominent Indian-origin athletes living abroad may be encouraged to come back and play for India at the international level. Together, these efforts can transform sport into a dynamic tool of cultural diplomacy and nation-building, strengthening the global Indian identity.
- (v) **Promotion of Sports & Allied Services as Mainstream Career:** To enhance the recognition and attractiveness of sports as a career option, it is important to promote sports professional education through structured frameworks and regulations. States and other stakeholders shall be encouraged to establish sports educational institutions which will provide more pathways into the industry. Creating resources to raise awareness about sports careers among youth, along with a national platform for sports certifications, degrees, courses and job vacancies, will help streamline career pathways. Dual-career programs will be promoted that balances academics and sports which will also support students in pursuing their athletic and educational goals simultaneously.
- (vi) **Sports Volunteering Programs:** Engaging the youth in sports volunteering can enhance community involvement and support various sporting schemes. Robust sports volunteering mechanisms, such as the Khelo India Sports Activator and FIT India Volunteer programs, will be established in order to encourage active participation. Recognizing and rewarding volunteers will be promoted through incentives like course credits, event passes and opportunities to meet champion athletes which will further motivate young individuals to contribute to the sports sector and foster a culture of volunteerism.

3.4 Sports – A People's Movement

Sports can transform into a powerful people's movement by addressing key aspects of physical and mental well-being while serving as a major leisure and entertainment activity. Prioritizing physical health through sports improves overall fitness, reduces healthcare costs and promotes a healthier lifestyle. Mental health benefits are also significant, as regular physical activity can reduce stress, anxiety and depression, while fostering a sense of community and belonging. Additionally, sports offer a valuable source of leisure and entertainment, enriching lives and enhancing quality of life.

- (i) To support this movement, a **Fitness Ranking & Indexing** system will be implemented to incentivize educational institutions and workplaces to excel in their sports and physical education programs. Mechanisms like the School Fitness Index and Fit Workplace Index will be developed to drive excellence and innovation in fitness initiatives. Furthermore, robust **Personnel Training & Certification** programs would be established as it is crucial for equipping trainers and educators with the skills necessary to deliver effective sports and Physical Education programs, enhancing health outcomes and talent identification.
- (ii) **National Sports Federations (NSFs)** shall be actively engaged with educational institutions to promote their disciplines and formulate frameworks focusing on physical and mental well-being. This will be achieved through initiatives such as School Soccer Programs and Tennis for Tots. Standard Operating Procedures (SOPs) would be created for **fitness programs** at schools, colleges and workplaces which will ensure structured and consistent delivery of fitness activities, supported by a resource repository like the FIT India Information & Knowledge Hub.
- (iii) **Physical Education Framework** will be revamped in collaboration with the Ministry of Education to enhance the effectiveness of physical education programs and improve talent development mechanisms.
- (iv) **Access to sporting facilities** will be improved through guidelines and frameworks that will facilitate greater public participation and support the establishment of social sports hubs at block and district levels.
- (v) **Model sports programs and events**, such as Family Sports Weekends and periodic community engagement activities will be encouraged to promote regular participation and foster a culture of active living. **Barriers to**

participation will be reduced and underutilized public facilities will be leveraged to further enhance accessibility. Finally, **national-level programs** and digital initiatives, like the Yoga Challenge and 10,000 Steps a Day Challenge, will be conducted which will drive large-scale engagement and cement sports as a central element of community life, transforming it into a true people's movement.

3.5 Major Focus Areas to Harmonize Khelo Bharat Niti-2025 with NEP 2020

To achieve alignment between the Khelo Bharat Niti-2025 and the National Education Policy (NEP) 2020, several key focus areas will be addressed. A framework and delivery of sports modules for the holistic education program will be facilitated to ensure that sports and physical education are integrated seamlessly into the overall curriculum. This approach will promote a balanced development of students, combining academic learning with physical fitness and personal growth.

- (i) A framework for the active engagement of sports groups and circles in educational institutions will be formulated to enhance the presence and impact of sports in schools. This shall involve establishing partnerships with local sports organizations and creating structured programs that encourage participation and talent development within educational settings.
- (ii) A sports and physical education skill development program for teachers will be framed and facilitated for the effective delivery of sports education. Providing educators with specialized training and resources will ensure they are well-equipped to teach and inspire students, thereby improving the quality of sports programs across schools.
- (iii) Liaising with various stakeholders to develop an action plan and timeline will be encouraged to address the infrastructure and resource needs for effective sports program delivery. This will include ensuring adequate manpower, securing necessary resources such as playgrounds, and implementing school-level programs on a regular basis. Coordinated efforts among government bodies, educational institutions and sports organizations will help achieve these objectives and create a sustainable framework for integrating sports into the educational landscape.

4. STRATEGIC FRAMEWORK FOR ACHIEVING THE OBJECTIVES OF KHELO BHARAT NITI-2025

The strategic framework outlines a comprehensive strategy to advance the sports ecosystem in India through robust governance, education, technological integration and private sector engagement. Key pillars of this framework include:

- (i) **Strong Professional Sports Governance, Implementation & Monitoring:** With a view to prepare India's sports ecosystem for Olympics 2036, the requisite regulatory framework including law, if required, for governance shall be established. In line with the international code on doping, a national law shall be enacted. National-level regulatory bodies and/or processes shall be established to ensure ethical practices, fair play and healthy competition in the sports sector. It will also involve the creation of national agencies and inter-ministerial committees to facilitate swift action and effective issue resolution, promoting transparency and seamless operations across the sports ecosystem.
- (ii) **Strong Sports Education, Research & Innovation Framework:** To place a significant emphasis on sports education, research and innovation to build a strong foundation for future athletes and sports professionals. It aims to encourage the development of research programs that foster innovation in areas such as sports training, management and infrastructure, ensuring a progressive and dynamic approach to the growth of the sports sector.
- (iii) **Technological Intervention:** Existing platforms will be revamped to enhance efficiency, transparency and effectiveness in implementing and monitoring various sports schemes and projects. By utilizing technology including artificial intelligence for data-driven analysis, it aims to monitor and analyze performance, enabling timely interventions for ongoing programs to ensure optimal outcomes and continual improvement in the sports sector.
- (iv) **National Framework & Regulatory Bodies:** A robust national structure with clear benchmarks, key performance indicators (KPIs) and time-bound targets will be established to guide the development of sports in the country. It will focus on holistic growth by encompassing grassroots development, elite athlete training and infrastructure enhancement. Additionally, it will support the organization of sports leagues at various levels, to ensure comprehensive and inclusive progress in the sporting ecosystem.
- (v) **Private Sector Engagement:** Policies and schemes will be developed to actively encourage extensive participation from the private sector in sports development activities. To incentivize this contribution, the

policy will incorporate Return on Investment (ROI) considerations for private entities, making their involvement in sports development both attractive and sustainable. This approach aims to foster a collaborative environment where the private sector plays a crucial role in advancing the country's sports infrastructure and programs.

5. CONCLUSION

- 5.1 The **Khelo Bharat Niti-2025** embodies a visionary and comprehensive framework aimed at revolutionizing sports development in India. It is designed to align sports advancement with the broader objectives of economic and social progress, leveraging sports as a powerful tool for nation-building. The policy adopts a multi-faceted strategy that addresses critical areas such as infrastructure development, talent identification, nurturing, governance reforms and enhancing mass participation. By improving sports facilities, creating robust talent pipelines, implementing governance reforms and encouraging widespread involvement, Khelo Bharat Niti-2025 aspires to elevate India to the status of a global sporting powerhouse to host major international sports events and also improve its participation as well as its medal tally in international sports competitions.
- 5.2 The Khelo Bharat Niti-2025 will serve as a model policy for States who shall be encouraged to modify their existing Sports Policy, if any, or adopt new Sports Policy in line with this policy. Further, following a whole of Government approach, this Policy needs implementation and integration by all Ministries/Departments in their work domain, policies, schemes, etc. to ensure promotion of sports.
- 5.3 Achieving the ambitious goals outlined by Khelo Bharat Niti-2025 will require a unified effort from all relevant stakeholders, including State Governments, government agencies, sports federations, private sector entities and the general public. Each stakeholder will play a crucial role in the successful execution of the policy's initiatives. Government agencies will provide the necessary regulatory framework and funding, sports federations will drive talent development and competition, the private sector will contribute resources and innovation, and the public will engage in and support sports activities. Through this collaborative approach, India has the potential to unlock its full sporting potential, setting the stage for a transformative impact on the nation's global standing in sports and contributing significantly to its overall development.

Dr. SHOBHIT JAIN, Jt. Secy.